

Seen
23/06/18

पत्र सं०-सी०/एल०ए०-०३/२०१८.....५७७९/जे०

बिहार सरकार
विधि विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,
बुद्धमार्ग, पटना।

पटना, दिनांक 27.06.18

विषय:- सी०डब्लू०जे०सी० सं०-३५५/१७ मुकेश रंजन बनाम बिहार सरकार एवं अन्य
में पारित न्याय निर्णय के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-८५०, दिनांक-३१.०३.२०१८

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विषयांकित वाद में आपके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वित्त विभाग से निम्न परामर्श प्राप्त हुआ:-

1. दिनांक-२०.१२.२००० के पूर्व नियुक्ति में ४०००-६०००/- एवं दिनांक-२१.१२.२००० से आगे की तिथियों में नियुक्ति के लिए ३०५०-४५९०/- का तैतनमान ही अनुमान्य होगा।
2. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा दिनांक-०१.०१.९६ के प्रभाव से Scale to Scale के बजाय Post to Post की अवधारणा के आधार पर वेतनमान की स्वीकृति कदी गई है। फिटमेंट कमिटी द्वारा दिनांक-०१.०१.१९९६ के प्रभाव से लिपिकीय संवर्ग के मूल कोर्ट के पद के लिए ३०५०-४५९० की अनुशंसा की गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। दिनांक-०१.०१.२००६ के प्रभाव से लिपिकीय मूल कोर्ट पद का वेतनमान पी०बी०-१ ग्रेड पे०-१९००/-स्वीकृत है। इसी आधार पर समूह 'ग' के सृजित पदों का ग्रेड पे०-१९०० निर्धारित किया गया है। अतः बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, १९९६ में लिपिक पद के लिए अंकित अपुनरीक्षित वेतनमान -१२००-१८०० के आधार पर ग्रेड पे०-२४००/- का दावा उचित नहीं है।
3. उक्त को दृष्टिपथ में रखते हुए सी०डब्लू०जे०सी० सं०-३५५/२०१७ में पारित आदेश के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि वित्त विभाग के उक्त परामर्श के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

22/6/18

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के प्रभारी सचिव, बिहार।

22/6/18

5142
22/6/18